National Journal of Advanced Research
Online ISSN: 2455-216X; Impact Factor: RJIF 5.12
www.allnationaljournal.com
Volume 3; Issue 2; May 2017; Page No. 62-66

कच्ची बस्तियों का उदय, उसमे रहने वाले लोगों कि स्थिति, उनकी समस्याएं व उनकी स्थिति सुधारने हेतु किये गये प्रयास : जयपुर नगर निगम के विशेष संदर्भ में

[1] नेहा शर्मा, [2] डॉ. रविन्द्र शर्मा

[1] शोधकत्री, लोक प्रशासन विभाग, ज्योति राव फूले विश्वविधालय, न्यू सांगानेर रोड़, जयपुर, भारत।
[2] आचार्य एवं पूर्व विभागाध्यक्ष, लोक प्रशासन विभाग, राजस्थान विश्वविधालय, जयपुर, भारत।

सारांश
भारत संसार का द्वितीय सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है जहां अभी भी बहुसंख्य लोग कच्ची बस्तियों में निवास करते हैं। रोजगार की तलाश में या उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिये ग्रामीणजन के शहरों में आने से नगरीय जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है। जिसके कारण कच्ची बस्तियो में रहने वाले लोगों की जनसंख्या भी तेजी से बढ़ती जा रही है। आज प्रगति की ओर विकसित हमारा देश कच्ची बस्तियों और उससे जुड़ी अनेकों समस्याओं की ओर भी बढ़ता जा रहा है जो की एक चिन्ता का विषय बन गया है। कच्ची बस्तियों में रहने वाले लोगों की स्थिति अत्यधिक दैनीय होती है। इनके पास न तो रहने के लिये घर होता है, और ना ही खाने के लिये पौषटिक आहार होता है। अपराध और उससे जुड़ी समस्याऐं कच्ची बस्तियों में आम बात है। इस लेख में जयपुर नगर निगम मे कच्ची बस्तियो की स्थिति का अध्ययन किया गया है।

मूल शब्द : कच्ची बस्तियों, जनसंख्या, जयपुर नगर निगम।

प्रस्तवना

कच्ची बस्तीयों की परिभाषा– रे के अनुसार कच्ची बस्तियों में कम से कम 20 मकानों का एक सघन बसाव है। जो कि अव्यवस्थित रूप से निर्मित मकानों का समूह है। जिनमें अधिकांश मकान अस्थायी स्वरूप के हैं, जिसमें अस्वस्थकर दशाओं में सामान्यतः अपर्याप्त सफाई व्यवस्था और पेयजल सुविधा होती है।[1]

इन्टरनेशनल जनरल ऑफ रिसर्च इन इकनोमिक्स एण्ड सोशल साईन्स के अनुसार (IJRESS)– गरीबी, जीर्ण, अधिक भीड़–भाड़ वाला क्षेत्र निम्न वर्ग की एकाग्रता, प्रजातीय प्रथकरण, अपराध, स्वास्थ्य सम्बंधी परेशानियॉं अन्य संक्रमण व अस्वास्थ्यकर वातावरण आदि के द्वारा कच्ची बस्तीयों को चित्रित किया गया है। विभिन्न देशों में विभिन्न शहरों में कच्ची बस्तीयों के लिए विभिन्न शब्द इस्तेमाल किये जाते हैं। भारत में भी यह कई नामों से जाना जाता है जैसे दिल्ली में इसे झोपड़पट्टी, मुम्बई में इसे चॉल व जयपुर में इसे कच्ची बस्ती कहा जाता है।[2]

रे के अनुसार कच्ची बस्तियों को कुछ भागों में बांटा गया है जैसे–

1. **टेनेबल स्लम–** जो बस्ती खतरनाक स्थिती संभावित स्थान पर बसावट ना हो, और किसी मास्टर प्लान के तहत मूलभूत सार्वजनिक सुविधाओं के लिए चयनित ना हो।
2. **अर्ध टेनेबल स्लम–** जो बस्ती प्लान के तहत गैर आवासीय भूमि क्षेत्र पर बसावट हो, और किसी खतरनाक स्थिती संभावित स्थान पर बसावट ना हो।
3. **गैर टेनेबल स्लम–** जो बस्ती खतरनाक स्थिती संभावित स्थान पर बसावट हो, जहॉं रहने पर लोगों के जीवन को खतरा हो और किसी मास्टर प्लान के तहत मूलभूत सार्वजनिक सुविधाओं के लिए चयनित हो।[3]

कच्ची बस्तियों के उदय और उनके बढ़ने के प्रमुख कारण

दुनिया के अलग–अलग हिस्सों में अलग–अलग कारणों से कच्ची बस्तियों का उदय होता है। जिससे दुनिया में कच्ची बस्तियों की संख्या व समस्या दोनों बढ़ती जा रही हैं।

i) **ग्रामीण लोगों का शहर में आकर बसना–** ग्रामीण लोगों का शहर में आकर बसना भी कच्ची बस्तियों के गठन व उनके विस्तार का एक कारण है। गांवो में खेती ही एक मात्र कमाई का साधन रहता है जबकि शहरों में आकर उन्हे कमाई के अनेक साधन प्राप्त हो जाते हैं। जिसके कारण वे अपना जीवन आसानी से बिता सकते हैं। नौकरियों के अलावा बेहतर शिक्षा पाने के लिए भी ये शहरों में आकर बस जाते हैं।[4] पैसों के अभाव के कारण ये लोग कच्ची बस्तियों में कम कीमते देकर रहते हैं।

ii) **खराब आवासीय योजना–** सस्ते व कम लागत वाले आवासों की कमी और योजना कच्ची बस्तियों को बढ़ाने में प्रोत्साहित करती है।[5] अपर्याप्त वित्तीय संसाधन और सरकार की नौकरशाही में समन्वय की कमी खराब आवासीय योजना के दो प्रमुख कारण है। सरकार बड़ी–बड़ी बाते तो करती है और बजट भी तैयार कर लिया जाता है लेकिन जितना पैसा मिलता है, उसका कुछ भाग ही योजनाओं को पूरा करने में लगाया जाता है बाकी का पैसा तो केवल नेताओं की जेब में जाता है परन्तु इसका भुगतान गरीब कच्ची बस्तियों में रहने वाले लोगों को करना पड़ता है।

iii) **गरीबी–** गरीबी कच्ची बस्तियों के गठन और मांग को प्रोत्साहित करती है।[6] गरीब लोग गरीबी के कारण अच्छी आधारभूत सुविधाऐं खरीदनें में समर्थ नहीं होते हैं। नौकरियॉं भी बहुत अच्छी नहीं मिल पाती हैं। ये केवल इतना ही कमा पाते हैं कि रोज कमा कर रोज खा सकें। ऐसे में अपने लिए सुविधाओं से युक्त घर की उम्मीद करना बेकार होता है। कच्ची बस्तियों में इनको अपनी आवश्यकता के अनुसार कम कीमत पर रहने के लिए घर मिल जाता है।

iv) **राजनीति–** स्थानीय व राष्ट्रीय सरकार के पास इतनी ताकत होती है कि वे अच्छी आवासीय योजना बनाकर कच्ची बस्तियों

में रहने वाले लोगों की व उनके आवासों की स्थिती में बेहतर सुधार कर सके।[7] देश में जब नेताओं को जीतने के लिए वोट लेने होते हैं तब इनको कच्ची बस्तियों में रहने वाले लोगों की याद आती है उनसे बड़े–बड़े वादे किए जाते हैं, बेहतर जीवन व अच्छे आवासीय योजना के सपने दिखाऐं जाते हैं परन्तु जीतने के बाद कोई इनको देखता भी नहीं है। सरकार योजनाऐं तो बनाती है पर केवल सरकारी किताबो में दिखाने के लिए, पर हकीकत कुछ और ही होती है।

v) **प्राकृतिक आपदा**– प्राकृतिक आपदा भी एक बड़ा कारण है कच्ची बस्तियों के बनने का। शहरों में बहुत से गरीब लोग ऐसे होते हैं जिनके पास पक्के मकान नहीं होते। ये लोग या तो टेन्ट या फिर कच्चे मकान बना कर रहते हैं[8] जो भूकम्प, अधिक बारिश आदि आने पर खराब हो जाते हैं, जिसके कारण ये लोग बेघर हो जाते हैं।

vi) **ामाजिक संघर्ष–** 1975 से 1990 तक गृहयुद्ध के दौरान लाखों लेबनानी लोगों ने कच्ची बस्तियों का गठन किया था।[9] इसी प्रकार हाल ही के वर्षों में ग्रामीण अफगान, तालिबान हिंसा से बचने के लिये काबुल में चारों तरफ बहुत सी कच्ची बस्तियों का गठन किया गया।[10] इस प्रकार सामाजिक संघर्ष भी कच्ची बस्तियों के बनने का प्रमुख कारण है।

कच्ची बस्ती क्षेत्रों के लक्षण एवं विशेषताऐं

कच्ची बस्तियों के कुछ लक्षण व विशेषताऐं हैं जो इस प्रकार है–

i) **स्थान व विकास–** कच्ची बस्तियां आमतौर पर शहरी इलाको के बाहरी क्षेत्र से शुरू हुये हैं। जो कच्ची बस्तियां अब बन रही हैं वे शहरी क्षेत्रों की सीमा में बन रही हैं। पहले कच्ची बस्तियां शहरों से बाहरी इलाको में होती थी परन्तु जैसे–जैसे समय बदलता जा रहा है, लोगों की जरूरते भी बढ़ती जा रही है। बाहरी क्षेत्रों में होने के कारण उन्हे अपनी जरूरत की चीजें शहरों में आकर लेनी पड़ती थी, जो कि उनके लिए और भी अधिक महंगा पड़ता था इसलिए ये लोग धीरे–धीरे करके शहरी क्षेत्रों में आकर बसने लगे, जिससे कच्ची बस्तियों का स्थान तो बदला ही साथ ही कच्ची बस्तियों का विकास भी होता गया।[11]

ii) **असुरक्षित कार्यकाल या पदावधि**– भूमि कार्यकाल की अनौपचारिकता शहरी कच्ची बस्तियों के लक्षण की चाबी है। कुछ मामलों में स्थानीय सरकार इन लोगों के लिए भूमि आवंटित करती है जो कि बाद में जाकर एक कच्ची बस्ती के रूप में विकसित हो जाती है। इसमें रहने वाले लोगों का इस सम्पत्ति पर कोई हक नहीं होता है। उन्हे वहाँ से कभी भी हटाया जा सकता है क्योंकि यह स्थान उन्हे सिर्फ रहने के लिए दिया जाता है। इस प्रवाह के कारण 51 प्रतिशत स्लम्स उपसाहारा अफ्रीका में निजी भूमि पर अतिक्रमित है, 40 प्रतिशत ईस्ट ऐशिया में और 40 प्रतिशत लैटिन अमेरिका और केरिबियन में।[12]

कच्ची बस्तियों की प्रमुख समस्याएं

कच्ची बस्तियों की कुछ समस्याएं ऐसी हैं जो दुनियाँ में सब जगह एक जैसी हैं जैसे–

i) **घटिया आवास व भीड़–भाड़–** कच्ची बस्तियों को खराब आवास संरचनाओं द्वारा विश्लेषित किया जाता है।[13] कच्ची बस्तियों में आवास प्राय अनुपयुक्त सामग्री से निर्मित किये जाते हैं। लोहे व शीटों के टुकड़ो, कागज, प्लास्टिक व मिट्टी आदि से बने इन घरों की अवधि ज्यादा नहीं होती। ये घर सुरक्षा की दृष्टि से असुरक्षित होते हैं। अत्यधिक भीड–भाड़ भी कच्ची बस्तियों की एक विशेषता है। कच्ची बस्तियों में रहने वाले लोगों के पास सामान्यतः एक ही कमरा होता है, जिसमे बहुत से लोग एक साथ रहते हैं।[14]

ii) **अपर्याप्ता और कोई बुनियादी सुविधा ना होना–** कच्ची बस्तियों की पहचान की विशेषताओं में से एक है अपर्याप्त सार्वजनिक बुनियादी ढांचे की कमी।[15] सुरक्षित पीने के पानी से लेकर बिजली तक, बुनियादी स्वास्थ्य से लेकर पुलिस सेवा तक, किफायती सार्वजनिक परिवहन से लेकर एम्बुलेंस सेवा तक, सफाई व्यवस्था से लेकर पक्की सड़को तक सभी आधारभूत सुविधाओं का अभाव होता है। आधारभूत सुविधाओं की कमी के कारण इनकी स्थिती खराब होती जा रही है। आग जैसी समस्याऐं यहां पर सबसे ज्यादा होती है।

जोखिम

कच्ची बस्तियों में रहने वाले लोगों को बहुत से जोखिमों का सामना भी करना पड़ता है। उनमें से कुछ इस प्रकार है–

i) **प्राकृतिक और अप्राकृतिक खतरों से जोखिम–** कच्ची बस्तियां अधिकतर ऐसे स्थानों पर होती है जहाँ प्राकृतिक आपदाओं का खतरा अधिक होता है।[16] शहरों में कच्ची बस्तियां अधिकतर रेलवे ट्रैक के पास, खराब व बंजर पड़ी खाली जगहों पर, सुखी नदियों के किनारे, कुड़ा–कचरा फैंकने के आस–पास के क्षेत्रों आदि जगहों पर देखने को मिलती है।[17] कुछ कच्ची बस्तियां मानव निर्मित खतरो के पास होती है जैसे विषाक्त कारखाने, यातायात, खराब पड़ी पुरानी ईमारते जो एकदम जरजर स्थिति में होती है। ये जगह खतरों से भरी होती है। सरकार को यह देखना आवश्यक है कि जब ये कच्ची बस्तियां छोटे रूप में यहाँ बसी होती हैं तभी उन्हे यहाँ से हटा देना चाहिए क्योंकि बड़ी होने के बाद उन्हे हटाना बहुत मुश्किल हो जाता है।

ii) **बेरोजगारी और अनौपचारिक अर्थव्यवस्था**– कौशल व शिक्षा की कमी के कारण कच्ची बस्तियों में रहने वाले लोगों को बहुत अधिक मात्रा में बेरोजगारी का सामना करना पड़ता है।[18] नौकरियों के अवसरों की कमी के कारण इनमें से बहुत से लोग अपने स्वयं का कार्य कर लेते हैं। यह कार्य या तो कच्ची बस्तियों के अन्दर करते हैं या कच्ची बस्तियों के पास विकसित शहरी क्षेत्रों में। इस प्रकार के कार्य अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में आते हैं। इस प्रकार के कार्यों में ना उन्हे किसी के साथ कोई कार्य का अनुबंध करना होता है और ना ही सामाजिक सुरक्षा की जरूरत पड़ती है। इनमें से कुछ लोग अनौपचारिक क्षेत्रों में व्यवसायिक कौशल पाने के बाद औपचारिक अर्थव्यवस्था में नौकरियाँ प्राप्त कर लेते हैं। कानूनी अनौपचारिक अर्थव्यवस्था के उदाहरण है सड़क, घरेलू उधमों, उत्पाद बनाना और पैकेजिंग, चिकनकारी, घरेलू काम, जुते चमकाना व मरम्मत करना, टुक–टुक गाड़ी चलाना या हाथगाड़ी वाला रिक्शा चलाना, हस्तशिल्प का कार्य आदि शामिल है।[19]

iii) **हिंसा–** कुछ विद्वानों का मानना है कि अपराध कच्ची बस्तियों की मुख्य समस्याओं में से एक है।[20] कुछ देश जैसे वेनेजुएला में कच्ची बस्तियों में आपराधिक हिंसा आम बात है।[21] कच्ची बस्तियां अधिकतर ऐसी जगहों पर होते हैं, जो पुरी तरह से असुरक्षित होते हैं। इससे सबसे ज्यादा खतरा महिलाओं को होता है। बलात्कार कच्ची बस्तियों में अपराध से सम्बंन्धित एक और गंभीर मुद्दा है। उदाहरण के लिये नैरोबी कच्ची बस्तियों में सभी किशोर लड़कियों में से एक चौथाई लड़कियाँ हर साल बलात्कार का शिकार होती हैं।[22] विकासशील देशों के मुख्य शहरों में शहरी विकास व कच्ची बस्तियों के विस्तार के पीछे कानून प्रवर्तन का पिछड़ना है। कच्ची बस्तियों में एक और बड़ी समस्या है, सशस्त्र हिंसा (बन्दूक हिंसा)। अमेरिका व लैटिन अमेरिका के कच्ची बस्तियों में इनका विस्तार सबसे ज्यादा है।[23]

iv) बीमारियाँ– कच्ची बस्तियों में रहने वाले लोग सामान्यता अधिक मात्रा में बिमारियों से ग्रसित होते हैं।[24] जैसे हैजा, एच.आई. वी/एड्स, डेंगू, टाइफाइड, दवा प्रतिरोधी तपेदिक और अन्य महामारियाँ।[25] एक अध्ययन के अनुसार नैरोबी की कच्ची बस्तियों में एच.आई.वी./एड्स और क्षय रोग जैसी बीमारियाँ 50 प्रतिशत मृत्युदर को बढ़ाने के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है।[26] कच्ची बस्तियों में रहने वाले बच्चों के स्वास्थ्य की ओर यदि ध्यान केन्द्रित करे तो यहां अधिकांश बच्चे कुपोषण से ग्रसित होते हैं।[27] दुनिया की अधिकांश कच्ची बस्तियों में स्वास्थ्य सेवा मौजुद नहीं होती है। कच्ची बस्तियों को महामारियों से ऐतिहासिक रूप से जोड़ा गया है।[28] आधुनिक समय में भी यह प्रथा चली आ रही है। उदाहरण के लिए पश्चिमी अफ्रीकी देशों की कच्ची बस्तियों जैसे लाइबेरिया का सन् 2014 में इबोला के प्रकोप का प्रसार करने में योगदान रहा है।[29]

भारत में कच्ची बस्तियों की जनसंख्या

सामान्यतया गरीबी की रेखा से नीचे आने वाले लोग कच्ची बस्ती क्षेत्रों में रहते हैं। सरकार के स्त्रोतों के अनुसार भारत में कच्ची बस्तियों की जनसंख्या ब्रिटेन की कुल जनसंख्या से अधिक है, जो पिछले दो दशकों में दौगुनी हो गयी है। भारत में कच्ची बस्तियों में रहने वाले लोगों की जनसंख्या 1981 में 27.9 मिलियन थी जो 2001 में 61.8 मिलियन हो गयी थी और 2011 में यह 93.06 मिलियन हो गयी है। एक अनुमान के अनुसार भारत में 2017 में कच्ची बस्तियों की जनसंख्या 104 मिलियन हो जावेगी।[30] 2011 के लिये प्राथमिक जनगणना के सार के अनुसार, राजस्थान में 20.68 लाख कच्ची बस्तियां दर्ज की गयी है। जनगणना 2011 के आकडों के अनुसार पूरे देश की कच्ची बस्तियों की जनसख्या में राजस्थान की कच्ची बस्तियों की भागीदारी 3.2 प्रतिशत है। राजस्थान में कच्ची बस्तियों में रहने वालो की संख्या पिछले जनगणना 2001 से जनगणना 2011 में 0.2 प्रतिशत की वृद्वि देखी गयी है।[31]

जयपुर शहर में कच्ची बस्तियों की संख्या व उनकी जनसंख्या

जयपुर जिले की जनसंख्या पूरे राजस्थान की जनसंख्या की 17 प्रतिशत है। 1951 से 2011 तक जयपुर राज्य की जनसंख्या 5 गुना बढ़ी है। सिटी डवलपमेन्ट प्लान (सी.डी.पी.) के अनुसार 1971 में पूरी जनसंख्या का 16 प्रतिशत कच्ची बस्तियों की जनसंख्या जयपुर में थी। 1971 में जयपुर में कच्ची बस्तियों की संख्या 109 थी, इसमें से 73 कच्ची बस्तियां अरबन इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट के अधिकार क्षेत्र में व 36 कच्ची बस्तियां नगर परिषद सीमा के अधिकार क्षेत्र में आती थी।[32] 1981 में कच्ची बस्तियों की संख्या में बढ़ोतरी नहीं हुई परन्तु कच्ची बस्तियों में रहने वाले लोगों की संख्या में इजाफा हुआ।[33] 2001 में कच्ची बस्तियों की संख्या 211 हो गई। नई बनी सभी कच्ची बस्तियां पर्यावरण की दृष्टी से संवेदनशील क्षेत्रों पर थी, जहां इन्हे काफी खतरा रहता था, जो किसी भी तरीके से रहने लायक जगह नहीं थी।[34] 2011 में जयपुर नगर निगम के अन्तर्गत 192 कच्ची बस्तियां व जयपुर विकास प्राधिकरण के अन्तर्गत 46 कच्ची बस्तियां थी, जो कि 2015 में बढ़कर जयपुर नगर निगम में 192 कच्ची बस्तियां व जयपुर विकास प्राधिकरण के अन्तर्गत 47 व गैर अधिसूचित कच्ची बस्तियां 20 हो गई।

जयपुर को नगर निगम द्वारा 8 जोनों में बांटा गया है।[35] जयपुर नगर निगम से मिली जानकारी के अनुसार सांगानेर जोन की कच्ची बस्तियों को छोड़कर 7 जोनों में स्थापित कच्ची बस्तियों की सूची यहां दी गई है–

1. विद्याधरनगर जोन में कच्ची बस्तियाँ
2. आमेर जोन में कच्ची बस्तियाँ
3. सिविल लाईन जोन में कच्ची बस्तियाँ
4. हवामहल जोन (ईस्ट)में कच्ची बस्तियाँ
5. हवामहल जोन (वेस्ट)में कच्ची बस्तियाँ
6. मानसरोवर जोन में कच्ची बस्तियाँ
7. मोती डूंगरी जोन में कच्ची बस्तियाँ

तालिका 1: गन्दी बस्तियों की जोनवार संख्या, परिवार व क्षेत्र

क.स.	जोन	नगर निगम/जेडीए	बस्तियों की संख्या	ज.वि.प्रा/.न.नि.ज	यशी संस्था	कुल कब्जे का क्षेत्र(हेक्टेयर)
1.	विधाधर नगर	ज.न.नि.	51	22116	26816	192.31
2.	आमेर	ज.न.नि.	19	2562	5079	53.91
3.	सिविल लाईन	ज.न.नि.	38	3682	13588	105.11
4.	हवामहल पूर्व	ज.न.नि.	13	1695	14214	109.24
5.	हवामहल पश्चिम	ज.न.नि.	33	2926	6057	49.29
6.	मोती डूंगरी	ज.न.नि.	31	12367	19239	115.94
7.	मानसरोवर	ज.न.नि.	7	1119	1851	15.82
8.	समस्त नोटीफाइड जोन	जे.डी.ए.	46+1	16968	22793	161.94
9.	समस्त गैर–नोटीफाइड जोन	जे.डी.ए.	20	––	4147	32.48
योग			258+1	63435	113784	836.03

स्त्रोत–जयपुर नगर निगम

जयपुर शहर में कच्ची बस्तियों के घरों की स्थिति

जनगणना 2011 के अनुसार जयपुर में कच्ची बस्तियों में 575,268 घर हैं। जिसमें से 2 प्रतिशत घर ऐसे हैं जो एकदम जीर्ण–शीर्ण स्थिति में हैं, जो किसी भी तरह से रहने लायक नहीं है। 93 प्रतिशत घर अध्कच्चे हैं तथा 5 प्रतिशत घर ही पक्के बने हुए हैं। 2001 के आकड़ों के अनुसार 3528 (0.95 प्रतिशत) घर अल्पकालिक (Temporary) थे व 15641 (4.22 प्रतिशत) घर स्थापित रुप से थे। 18 प्रतिशत के आस–पास शहरी लोग किराये के मकानों में रहते थे। 1991 में यह जनसख्या 31 प्रतिशत थी जो कि अब 2011 में घट कर 18.2 प्रतिशत हो गयी है।

जयपुर नगर निगम द्वारा चलाये जाने वाले कार्यक्रम

जयपुर नगर निगम द्वारा कच्ची बस्तियों की स्थिति सुंधारने के लिय जयपुर नगर निगम द्वारा अनके कार्यक्रम चलाये जाते हैं जैसे–

i) राजीव आवास योजना (Rajiv Awas Yojna)– इस योजना को संक्षेप में 'रे' के नाम से पुकारा जाता है। राजीव आवास योजना ने इस दिशा में अपने कदम उठाते हुये 4 जून, 2009 को राष्ट्रपति द्वारा इस योजना की घोषणा की गई थी। इस योजना

के द्वारा कच्ची बस्तियों में रहने वाले लोगों को उचित सुविधाऐं देकर, रहने के लिए घर देकर, देश को कच्ची बस्तियों से मुक्त कराने की कोशिश की गयी है। जयपुर शहर में रे (RAY) के अर्न्तगत निम्न 3 योजनाओं पर कार्य हुआ है–

(i) किरो की ढानी

(ii) संजय नगर भट्टा बस्ती

(iii) बगराना कच्ची बस्ती

इसमें से संजय नगर भट्टा बस्ती पर जयपुर नगर निगम द्वारा कार्य किया गया है। इस योजना के प्रथम फैज में 2212 डुप्लेक्स हाउस एवं 120 रेन्टल हाउसेस आधारभूत सुंविधाओं सहित विकसित किया जाना था। इस योजना के प्रथम फैज के लिये 96.61 करोड़ रुपये की स्वीकृती प्रदान की गई थी।[36] इस योजना की स्वीकृत राशि में केन्द्र व राज्य सरकार की 50 व 30 प्रतिशत एवं जयपुर नगर निगम की 20 प्रतिशत (हाउसिंग हेतु लाभार्थी हिस्सा 10 प्रतिशत सहित) हिस्सेदारी तय की गयी थी। वर्ष 2013 में इस योजना को स्वीकृति प्रदान की गयी परन्तु इस योजना पर जयपुर नगर निगम द्वारा कार्य पूरा नहीं किया गया और वर्ष 2015 में इसे बन्द कर दिया गया।

ii) जवाहरलाल नेहरु शहरी नवीनीकरण मिशन (JNNURM)– इस मिशन के अन्तर्गत दो उप घटक हैं–

(i) शहरी इन्फ्रास्ट्रक्चर एवं गवर्नेस (UIG)

(ii) शहरी गरीबों को मूलभूत सेवायें (BSUP)

इस योजना में BSUP के अन्तर्गत जयपुर शहर में 14 कच्ची बस्तियां(झालाना महल कुण्डा, कचरा बस्ती, राजीवपुरी, जेपी कॉलोनी, कागदीवाड़ा मद्रासी ढावा बजरंग विहार, कागदीवाड़ा नियर क्रीमेशन लेण्ड, गुर्जर घाटी कच्ची बस्ती, भौमिया बस्ती, नाहरगढ हरिजन कच्ची बस्ती, पर्वतपुरा, नर्सिंग कॉलोनी, जयसिंहपुरा खुर्द, आमगढ देहपुरी, खारवाल बस्ती) के रिलोकेशन का कार्य जयपुर नगर निगम के द्वारा किया जाना था, परन्तु नगर निगम के द्वारा इस योजना में कोई भी कार्य नहीं किया गया।[37] वर्ष 2015 में इस योजना को समाप्त कर इसके स्थान पर अमृत योजना को शुरु किया गया है।

iii) मुख्यमंत्री शहरी बीपीएल (BPL) आवास योजना– नगरीय क्षेत्रों में बीपीएल परिवारों की आवास सम्बंधी समस्याओं के समाधान हेतु माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा वित्तीय वर्ष 2012–13 की बजट घोषणा संख्या 172 में मुख्यमंत्री शहरी बीपीएल आवास योजना की घोषणा की गयी थी। इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 2012–13 में मुख्यमंत्री शहरी बी.पी.एल. आवास योजना के अन्तर्गत निवास की निजी भूमि एंव राजकीय स्वामित्व की भूमि पर अवास निर्माण या उन्नयन हेतु सहायता दी जायेगी। जयपुर नगर निगम द्वारा इस योजना के अन्तर्गत कोई कार्य नहीं किया गया।[38] वर्ष 2015 में इसे बन्द कर दिया गया था।

iv) प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY)– माननीय प्रधानमंत्री ने राष्ट्र की स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूर्ण हो जाने पर वर्ष 2022 तक सभी के लिये आवास की परिकल्पना की है। इस उदेश्य की प्राप्ति के लिये केन्द्र सरकार ने एक व्यापक मिशन "2022 तक सबके लिये आवास" शुरु किया है। 25 जून 2015 को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस बहुप्रतीक्षित योजना को प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम से प्रारम्भ किया है।[39]

जयपुर जिले में जयपुर विकास प्राधिकरण और जयपुर नगर निगम दोनों को इस योजना के अर्न्तगत शामिल किया गया है। जयपुर विकास प्राधिकरण ने इस पर अपना कार्य भी प्रारम्भ कर दिया है तथा ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया भी शुरु कर दी है। जयपुर नगर निगम के द्वारा इस पर अभी तक कोई कार्य नहीं किया गया है।

v) मुख्यमंत्री जन आवास योजना– केन्द्र सरकार की हाउसिंग फॉर ऑल मिशन को पूरा करने की मुहिम में राज्य सरकार ने कवायद शुरु कर दी है। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने सबके आवास का सपना साकार करने के लिये मुख्यमंत्री जन आवास योजना शुरु की है। इस योजना के तहत आवासन मण्डल, यूआईटी व विकास प्राधिकरण के अलावा निजी खातेदारों या विकासकर्ताओं के माध्यम से गरीब वर्ग के लिये सस्ती दरों पर प्रदेश में करीब साढ़े 10 लाख आवास बनवाये जायेंगे। सचिवालय स्थित मुख्यमंत्री कार्यालय में मुख्यमंत्री ने जन आवास योजना भी लांच की है। रिसर्जेंट राजस्थान को घ्यान में रखते हुये इस भू–आवंटन नीति को तैयार किया गया है।[40] जयपुर जिले में जयपुर विकास प्राधिकरण और जयपुर नगर निगम दोनों को इस योजना के अर्न्तगत शामिल किया गया है। जयपुर नगर निगम के द्वारा इस पर अभी तक कोई कार्य नहीं किया गया है।

अतः जयपुर नगर निगम जयपुर शहर को कच्ची बस्तियों सें मुक्त करने में पूरी तरह से असफल रहा है।

संन्दर्भ सूची

1. (RAY) Rajiv Awas Yojna Guidelines on Community Participation, Ministry of Housing & Urban Poverty Alleviation Government of India. 2011.
2. International Journal of Resrarch in Economic & Social Science (Need Assessment for urban Health in slums of Jaipur) Dr. Manoj Kumar. 2013, 3(1).
3. राजीव आवास योजना ;एक स्लम मुक्त भारत की औरद्ध जयपुर नगर निगम रिर्पोट] 2013
4. Jump up^ Urban Poverty-An Overview Judy Baker, The World Bank. 2008.
5. Jump up to:[a] [b] [c] Istanbul's Gecekondus Orhan Esen, London School of Economics and Political Science. 2009.
6. Jump up^ slums of the world: The face of urban poverty in the new millennium?, ISBN 92-1-131683-9, UN-Habitat
7. ^Jump up to:[a] [b] [c] Assessing Slums in the Development Context United Nations Habitat Group. 2011.
8. Jump up^ Slum upgrading-Why do slums develop Cities Alliance. 2011.
9. Jump up^ Slums – Summary of City Case Studies UN-Habitat. 203.
10. Jump up^Fleeing war, finding misery The plight of the internally displaced in Afghanistan Amnesty International. 2012, 9-12.
11. ^Jump up to:[a] [b] [c]def Rosa Flores Fernandez. Physical and Spatial Characteristics of Slum Territories Vulnerable to Natural Disasters, Les Chaiers d' Afrique de I' Est, n 44, French Institute for Research in Africa. 2011.
12. Jump up^Flood, Joe. Secure Tensure Survey Final Report. Urban Growth Management Initiative. 2006.
13. Jump up^ Kristof FS. Housing Policy goals and the turnover of housing. Journal of the American institute of planners. 1965; 31(3):232-245.
14. ^Jump up to:[a] [b] [c] UN-HABITAT 2007 Press Release on its report, "The Challenge of Slums: Global Report on Human Settlements. 2003.
15. Jump up^ Kenya Slum Upgrading Project United Nations Habitat. 2011.
16. Jump up^ Smith, Keith. Environmental hazards: assessing risk and reducing disaster, Routledge. 2013. ISBN 978-0415681056

17. ^Jump up to:[a] [b] Banerji M. Provision of basic services in the slums and resettlement colonies of Delhi, Institute of Social Studies Trust. 2009.
18. Jump up^ Slum residence World Health Oraganization. 2010.
19. Jump up^ Taj Ganj Slim Housing, Cities Alliance. 2012.
20. Jump up^ Kabiru CW *et al*. Making it": understanding adolescent resilience in two informal settlements (Slums) in Nairobi, Kenya. Child & Youth Services. 2012; 33(1):12-32.
21. Jump up^Venezuela's military enters high crime slums Karl Ritter, Associated Press. 2013.
22. Jump up^ Newar, Rachel. In Kenya, Where One in Four Women has Been Raped, Self Defense Training Makes a Difference. Smithsonian Magazine. Retrieved. 2013.
23. Jump up^ Palus, Nancy. "Humanitarian intervention in violence-hit slums – from whether to how". IRIN. Retrieved. 2013.
24. Jump up to:[a] [b] More Slums Equal More Violence Robert Muggah and Anna Alvazzi del Frate, Geneva Declaration on Armed Violence and Development & UNDP. 2007.
25. Jump up^ Victoriano A *et al*.. Leptospirosis in the Asia Pacific region. BMC Infectious Diseases. 2009; 9(1):147.
26. ^Jump up to:[a] [b]cd Ghosh S, Shah D. Nutritional problems in urban slum children". Indian Pediatr. 2004; 41(7):682-96.
27. Jump up^ Kyobutungi, Catherine *et al*. The burden of disease profile of residents of Nairobi's slums: Results from a Demographic Surveillance System". Population Health Metrics. 2008, 6(1).
28. Jump up^ Reiter P, Goh KT. Denjue control in Singapore, Denjue in Singapore. 1998, 213-242, ISNB 981-04-0164-7
29. Jump up^ In a Liberian swarming with Ebola, a race against time to save to little girls. The Washington Post
30. The Times of India, by 2017, India's slum population will rise to 104 million. 2013.
31. WWW. Rajcensus.Gov.in
32. Ramesh Arora K. Jaipur Profile of a Changing City Indian Institute of Public Administration Rajasthan Branch, The HCM State Institute of Public Administration, Jaipur. 1977.
33. Yadav CS. Slums-Urban Decline And Revitalisation (Socio-Economic Profile of Urban Slums-A Case study of Jaipur City), Concept Publishing Company, New Delhi. 1987, 260.
34. Dr. Ambey Kumar Srivastava. Leaders of Slum Dwellers-A study based on slums of Jaipur city IOSR Journal of Humanities and Social Science. 2013; 8(2):18-24.
35. http://www.jaipurmc.org
36. www.rajivawasyojna.in
37. जयपुर नगर निगम का वर्ष 2015–2016 का बजट अभिभाषण एवं आय–व्यय का अनुमान
38. जयपुर नगर निगम का वर्ष 2014–15 का बजट अभिभाषण एवं आय–व्यय का अनुमान
39. www.pmawasyojana.in
40. www.pmindia.gov.in